Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025

PopularFrontofIndiaOfficial/ www.popularfrontindia.org

popularfrontmail@gmail.com 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

5 अगस्त 2019
नई दिल्ली

पॉपुलर फ्रंट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक;
हालिया सभी कानून लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन
असम और कश्मीर के खराब होते हालात पर जताई चिंता

केरल के कालीकट में 3 और 4 अगस्त को आयोजित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक ने कहा कि बीजेपी संसद में पार्टी को प्राप्त बहुमत का दुरुपयोग करते हुए ऐसे दमनकारी कानून बना रही है जो मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यूएपीए संशोधन बिल 2019, एनआईए बिल 2019, आरटीआई संशोधन बिल 2019 और तीन तलाक बिल जैसे दीर्घकालिक प्रभाव रखने वाले कई कानून सिर्फ कुछ ही दिनों में संसद में पास कर दिए गए। जिस तरीके से सभी बिलों को बिना संसदीय छानबीन और बिल के खिलाफ उठाए गए गंभीर सवालों पर बिना विचार किए पास किया गया, वह इस बात का खुला इशारा है कि बीजेपी लोकतंत्र की रूह के खिलाफ अपनी बहुमत का दुरुपयोग कर रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है।

बिलों के प्रति विपक्षी दलों का स्टैंड धोखे पर आधारित

बैठक ने संसद में बिलों के प्रति विपक्षी दलों के सदस्यों के कपटी स्टैंड पर भी सवाल उठाया। विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने बिलों के खिलाफ खुलकर बात की और उन्होंने इस बात की शिकायत की कि 14 बिल बिना किसी छानबीन के बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी पास कर दिए गए। लेकिन जब वोटिंग का समय आया तो उनमें से अधिकतर ने दोनों सदनों में बिलों के हक में वोट दिया। बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद भी वह दोनों सदनों में बिलों को पास कराने में सफल रही। कुछ को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों ने इस बात का सबूत दिया है कि वे या तो बेहिस हो चुके हैं या बीजेपी से भयभीत हैं।

विपक्षी दलों को खत्म करने की बीजेपी की कोशिश

बैठक ने बीजेपी की राजनीतिक अनैतिकता पर चिंता व्यक्त की है जो कि दूसरी पार्टियों के सांसदों और विधायकों को खरीद रही है और ऐसा करके गैर–बीजेपी शासित राज्यों में राजनीतिक संकट की परिस्थिति पैदा कर रही है। यह बड़ी शर्मनाक बात है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों के बिकाऊ लोगों ने भी जनता और उसूलों के साथ धोखाधड़ी की

है। उन्होंने कर्नाटक की चयनित सरकार को गिरा दिया। अन्य राज्यों में भी दूसरी पार्टियों के सांसद और विधायक पैसे और दूसरे फायदों के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सत्ता के भूखे नेताओं का फायदा उठाकर और जनता की लोकतांत्रिक चाहतों को इस तरह से तबाह करके बीजेपी यह साबित कर रही है कि दूसरी पार्टियों को बर्बाद करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस तरह वह बिना कोई विपक्ष वाला अपाहिज लोकतंत्र बनाने की चाहत रखती है। बैठक ने दूसरी पार्टियों से यह अपील की है कि वे खुद को मजबूत करके और ऐसे नेताओं को चुनकर जो सत्ता और दौलत के बजाय जनता और उसूलों के प्रति प्रतिबद्ध हों, बीजेपी की शैतानी चालों का मुकाबला करें और उन्हें पराजित करें।

असम एनआरसीः मानवीय तबाही का कारण बनने वाली कुव्यवस्था को रोको

जैसा कि एनआरसी की फाइनल लिस्ट प्रकाशित करने की सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई आखरी तारीख में केवल कुछ ही सप्ताह रह गए हैं, ज़मीनी स्तर पर असम के हालात यह बताते हैं कि राज्य में जबरदस्त इंसानी तबाही का खतरा मंडरा रहा है, जहां लाखों लोग सरकारी तौर पर अपनी नागरिकता खो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 3.9 लाख लोग लिस्ट में शामिल होने के लिए अब तक अपने दावे और आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए हैं। वहीं कई जगहों से यह रिपोर्ट भी आ रही है कि जो लोग पहले से ही एनआरसी लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं, उनकी भी एक बड़ी संख्या को नागरिकता के रिकार्ड्स की दोबारा पुष्टि कराने के लिए कहा जा रहा है। दूसरे शब्दों में अगर फाइनल लिस्ट तय किए गए समय पर जारी कर दी गई, तो लाखों लोग बेवतन हो जाएंगे और उन्हें कोई नागरिक अधिकार हासिल नहीं होगा। पॉपुलर फ्रंट की एनईसी सुप्रीम कोर्ट से यह अपील करती है कि वह असम में गृहयुद्ध की परिस्थिति से बचने के लिए इस समस्या का कोई और आसान समाधान तलाश करें।

कश्मीरः हालात को बदतर होने से बचाओ

पॉपुलर फ्रंट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक ने जम्मू कश्मीर के बदतर होते हालात पर सख्त नाराजगी और चिंता जताई है। हालिया समय में टकराव और हत्या की बढ़ती घटनाओं, अतिरिक्त सैन्य बल की तैनाती, अमरनाथ यात्रा का टलना, छात्रों और पर्यटकों को इलाका खाली करने के लिए कहना जैसी बातों ने राज्य में बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। रिपोर्ट कहती है कि सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां और जनता केंद्र सरकार के प्रति अधिक दुश्मनी अपना चुकी हैं। बैठक ने इस ओर इशारा किया कि कश्मीर की समस्या का हल वहां की जनता को भरोसे में लेकर ही निकाला जा सकता है। दशकों पुरानी इस जटिल समस्या का स्थाई हल सैन्य बल के प्रदर्शन से नहीं निकाला जा सकता। बैठक ने कहा कि इसके बजाय सही राजनीतिक समझदारी यह है कि जम्मू–कश्मीर की जनता के सभी सही वर्गों के साथ बातचीत की तरफ लौटा जाए।

उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत

बैठक ने उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ताकतवर अपराधियों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही रेप पीड़िता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आशा की किरण जगाने वाला है। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में एक लड़की और उसके

परिवार का घोर अन्याय का सामना करना इस बात का सुबूत है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में नोटिस लेते हुए उसे दिल्ली ट्रांसफर करना पड़ा। उच्चतम न्यायालय ने सीआरपीएफ को पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट को यूपी सरकार और वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं है। इस फैसले की रोशनी में हम यूपी सरकार से यह मांग करते हैं कि वह अत्याचार को बढ़ावा देना और अपराधियों को सुरक्षा देना बंद करे।

ईरान के खिलाफ अमेरिकी कोशिशों की निंदा

एनडीसी की बैठक ने यह पाया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और उसके साथी देशों की बढ़ती दुश्मनी क्षेत्र में एक और देश को कमजोर और तबाह करने की कोशिश का हिस्सा है। जहां बातचीत के द्वारा समस्या के शांतिपूर्वक हल का अवसर मौजूद है, वहां 2015 के परमाणु सौदे से अमेरिका का एकतरफा तौर पर पीछे हटना और तेहरान पर दोबारा आर्थिक पाबंदियां लगाना इस बात का इशारा है कि अमेरिका शांति नहीं चाहता है। ईरान के बाद ब्रिटेन के द्वारा जहाजों पर कब्जे ने पूरे इलाके में युद्ध का माहौल पैदा कर दिया है। हम वैश्विक नेताओं से अपील करते हैं कि वे इस समस्या का शांतिपूर्वक हल तलाश करें ताकि क्षेत्र में एक और खूनी बर्बादी ना होने पाए।

चेयरमैन ई. अबूबकर ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें महासचिव एम. मोहम्मद अली जिन्ना उप–चेयरमैन ओ.एम.ए. सलाम, सचिव अनीस अहमद व अब्दुल वाहिद सेठ और राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य ई.एम. अब्दुर्रहमान, प्रोफेसर पी. कोया, एड० ए. मोहम्मद यूसुफ, ए.एस. इस्माइल, मोहम्मद रोशन, एम. अब्दुस्समद, मोहम्मद इस्माइल व अन्य उपस्थित रहे।

मोहम्मद अली जिन्ना
महासचिव
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया